

Daily करेंट अफेयर्स

» 11 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. पंजाब PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय शिक्षण परिणाम रैंकिंग में अग्रणी रहा।



जुलाई 2025 की शुरुआत में, पंजाब, स्कूली शिक्षा के आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों में उत्कृष्ट छात्र प्रदर्शन को दर्शाते हुए, PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 रिपोर्ट में देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के अब तक के सबसे बड़े योग्यता-आधारित शिक्षण मूल्यांकन का हिस्सा है।

- पंजाब ने कक्षा 3 के मूल्यांकन में 80 का उल्लेखनीय स्कोर हासिल किया, जिससे हिमाचल प्रदेश (74) और केरल (73) से आगे निकल गया और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। कक्षा 6 में, पंजाब 67 अंकों के साथ केरल के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कक्षा 9 में, यह 57 अंकों के साथ एक बार फिर शीर्ष पर रहा—जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्कोर है।

- PARAKH Rashtriya Sarvekshan, NCERT द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित एक सशक्त, प्रणाली-स्तरीय सर्वेक्षण है, जिसमें देश भर के 781 जिलों के 74,229 स्कूलों के कक्षा 3, 6 और 9 के 21 लाख से ज्यादा छात्र शामिल थे। यह NEP 2020 के चरण-वार आधारभूत शिक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाकर पिछले NAS आकलनों से एक बदलाव का प्रतीक है।

Key Points:-

(i) पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सार्वजनिक रूप से इस सफलता का श्रेय मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधारों को दिया, जिसमें बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन आवंटन और छात्र मार्गदर्शन शामिल हैं। राज्य के 845 सरकारी स्कूलों के छात्रों ने नीट और 265 ने जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण की, जो व्यापक शैक्षणिक उत्कृष्टता का संकेत है।

(ii) पंजाब के अनुकरणीय परिणामों के बावजूद, परख रिपोर्ट चेतावनी का संकेत देती है: इसने पूरे भारत में कक्षा 3 से कक्षा 9 तक औसत प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की, जहाँ गणित में शुरुआती कक्षाओं में केवल 60 प्रतिशत औसत था, जो कक्षा 9 तक गिरकर 37 प्रतिशत रह गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच भी लगातार अंतर देखा गया।

(iii) आगे बढ़ते हुए, PARAKH डेटा-आधारित, जिला-स्तरीय हस्तक्षेपों की सिफारिश करता है, जिसमें निपुण भारत के माध्यम से आधारभूत शिक्षा को मज़बूत करने, पिछड़े छात्र समूहों के लिए लक्षित सहायता और स्थानीय शैक्षिक योजना बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। पंजाब का अग्रणी प्रदर्शन समग्र शिक्षण परिणामों को आगे बढ़ाने वाले अन्य राज्यों के लिए एक खाका तैयार करने की उम्मीद है।

2. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने एक दशक में सौर ऊर्जा में 4,000% की वृद्धि हासिल की है।



केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जुलाई 2025 में 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह (IESW) में घोषणा की कि भारत की स्थापित सौर क्षमता पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से 4,000% बढ़ी है, जो अब 227GW कुल नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में योगदान दे रही है, जिससे भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी बन गया है।

● भारत के सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण में पिछले दस वर्षों में मॉड्यूल क्षमता में 38 गुना और सेल उत्पादन में 21 गुना वृद्धि देखी गई है। पीएम सूर्य गृह और पीएम कुसुम जैसी पहलों से समर्थित यह विनिर्माण वृद्धि अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के प्रयासों का समर्थन करती है।

● पीयूष गोयल ने सौर ऊर्जा अपनाने की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत संभवतः अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पल्ली गाँव का भी उल्लेख किया, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत है।

Key Points:-

(i) भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 227 गीगावाट है। हालाँकि, गोयल ने जोर देकर कहा कि बैटरी और पंप हाइड्रो से लेकर भू-तापीय और

परमाणु ऊर्जा तक, भंडारण समाधानों को तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 24x7 स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

(ii) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगली पीढ़ी की रसायन विज्ञान, सॉलिड-स्टेट सिस्टम और रीसाइक्लिंग रणनीतियों जैसी उन्नत बैटरी तकनीकों के लिए ₹1 लाख करोड़ (लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर) के अनुसंधान एवं विकास नवाचार कोष को मंजूरी दी है। गोयल ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत के नेतृत्व को मज़बूत करने के लिए कच्चे माल से लेकर रीसाइक्लिंग तक आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने का आह्वान किया।

(iii) स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए, गोयल ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वेपिंग नेटवर्क के लिए सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने चार-आयामी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की: नवाचार, बुनियादी ढाँचा विकास, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएँ और मूल्य श्रृंखला एकीकरण—जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आवश्यक हैं।

3. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनन प्रभावित जिलों के लिए 32,000 करोड़ रुपये के 'आकांक्षी DMF कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।



9 जुलाई, 2025 को, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय DMF कार्यशाला में आकांक्षी DMF कार्यक्रम का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय प्रमुख योजनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के धन को भारत के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की ओर रणनीतिक रूप से निर्देशित करना है।

- मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित DMF खातों में वर्तमान में ₹32,000 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध है। यह योजना निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें जिला कलेक्टरों को कार्य योजनाएँ तैयार करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

- जी किशन रेड्डी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, डीएमएफ फंड में ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा हो चुकी है, जिसमें से लगभग ₹90,000 करोड़ विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने पारदर्शिता, परियोजना ट्रैकिंग और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि यह राशि खनन प्रभावित समुदायों को सीधे लाभ पहुँचाए।

Key Points:-

(i) यह कार्यक्रम DMF-वित्त पोषित परियोजनाओं और जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बीच प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अंतर्गत अभिसरण को प्रोत्साहित करता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण जिला-स्तरीय खनिज कल्याण को भारत के व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

(ii) कार्यान्वयन में कमियों को दूर करते हुए, रेड्डी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे खनन प्रभावित जिलों से DMF संसाधनों को स्थानांतरित करने से बचें और लंबित परियोजनाओं, विशेष रूप से 143 बंद कोयला खदानों में खदान बंद करने के कार्य को पूरा करें। उन्होंने कार्यान्वयन और जवाबदेही के लिए जिला कलेक्टरों की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया।

(iii) स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यशाला में 62 जिला कलेक्टरों, राज्य DMF नोडल अधिकारियों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही, DMF द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना था।

4. नेस्ट्स और UNICEF ने EMRS के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'तलाश' कार्यक्रम शुरू किया।



10 जुलाई, 2025 को, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से, तलाश नामक एक अभिनव डिजिटल पहल शुरू की, जिसका नाम है जनजातीय योग्यता, जीवन कौशल और आत्म-सम्मान हब।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में समग्र विकास को बढ़ावा देकर आदिवासी छात्रों के शैक्षिक अनुभव को बदलना है।

- तलाश को विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के लिए आत्म-खोज, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन हेतु एक व्यापक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल उपकरणों को जीवन-कौशल मॉड्यूल के साथ जोड़कर, यह ईएमआरएस में नामांकित छात्रों में आत्म-जागरूकता को मज़बूत करने, आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है।

- तलाश का दायरा व्यापक है: इससे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ईएमआरएस में पढ़ रहे 1,38,000 से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा। शुभारंभ के दौरान, यह घोषणा की गई कि यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, और 75 स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पहले ही पूरा हो चुका है।

Key Points:-

(i) वर्तमान में, 75 EMRSs के 189 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वे अपने-अपने स्कूलों में तलाश सत्र आयोजित कर रहे हैं। 2025 के अंत तक, इस पहल का लक्ष्य सभी ईएमआरएस में कार्यरत होना है, जहाँ छात्रों को नियमित डिजिटल मार्गदर्शन और सलाह प्रदान की जाएगी।

(ii) यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जो शिक्षा से परे समग्र विकास पर ज़ोर देती है। एनईएसटीएस आयुक्त अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि तलाश आदिवासी युवाओं को "अपनी पूरी क्षमता का एहसास" कराने के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(iii) यह साझेदारी दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी और साक्ष्य-आधारित उपकरणों का भी लाभ उठाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन-कौशल प्रशिक्षण तक समान पहुँच प्राप्त हो। नियमित प्रतिक्रिया और मूल्यांकन तंत्र इस प्लेटफ़ॉर्म को छात्रों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार परिष्कृत और अनुकूलित करने में सक्षम बनाएगा।

5. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का शोषण करने वाले फर्जी संतों से निपटने के लिए 'ऑपरेशन कालनेमि' शुरू किया।



जुलाई 2025 में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमि की शुरुआत की, जो एक राज्यव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य साधु-संतों के वेश में धार्मिक भावनाओं का शोषण करके श्रद्धालुओं को ठगने वाले ठोंगियों का सफाया करना है, खासकर कांवड़ यात्रा के मौसम में। यह अभियान "देवभूमि" (देवताओं की भूमि) की पवित्रता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- इस अभियान का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस कालनेमि से लिया गया है, जिसने भगवान हनुमान को गुमराह करने के लिए खुद को एक संत का वेश धारण किया था। धामी ने आज के धोखेबाज धार्मिक नेताओं की तुलना आधुनिक कालनेमियों से की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपराधिक गतिविधियों के लिए धार्मिक पहचान का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।

- अभियान के पहले दिन, उत्तराखंड भर में पुलिस ने देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में साधुओं का वेश धारण किए 23-25 लोगों को गिरफ्तार किया—जिनमें से एक 26 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक भी था। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया, और अवैध प्रवासियों पर विदेशी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तीर्थस्थलों, धार्मिक स्थलों और कादियों (तीर्थयात्रियों के शिविरों) पर सादे कपड़ों में तैनात अधिकारियों को तैनात किया, जो नकली आध्यात्मिक साधकों की पहचान करने के लिए उनकी साख की जाँच और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे थे। सच्चे संतों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विश्वास बहाल करने और सच्ची आध्यात्मिक परंपराओं की छवि को बनाए रखने में मदद मिली है।

Key Points:-

(i) यह कार्रवाई कांवड़ यात्रा से ठीक पहले की गई है, जिसके लिए हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। बढ़ी हुई सतर्कता और पुलिस तैनाती के साथ, मुख्यमंत्री धामी ने ज़ोर देकर कहा कि धार्मिक पहचान के आधार पर कोई अपवाद नहीं किया जाएगा, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया जा सके।

(ii) इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों से मिल रहा मज़बूत समर्थन और नागरिकों से संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने का आग्रह करने वाली सलाह है। अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नकली संतों को मिलने वाली दंडमुक्ति, विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों जैसे कमज़ोर समूहों के बीच, वित्तीय शोषण और नैतिक क्षति को बढ़ावा देती है।

(iii) उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा सीजन के बाद भी ऑपरेशन कालनेमि जारी रखने का संकल्प लिया है। अकेले हरिद्वार में ही 12 जुलाई तक लगभग 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है, और दोबारा अपराध न हो, इसके लिए कठोर दस्तावेज़ीकरण और पृष्ठभूमि सत्यापन का काम चल रहा है।

6. एच.डी. कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में MSTC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और उपकरण व्यापार को डिजिटल बनाने के लिए 'उपकरण' ई-पोर्टल लॉन्च किया।



जुलाई 2025 में, केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जो इस्पात मंत्रालय (MoS) और भारी उद्योग मंत्रालय (MoHI) के प्रमुख हैं, ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) के नरोजीनगर में MSTC लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 'उपकरण' ई-पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए उपकरण व्यापार और इन्वेंट्री प्रबंधन में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख डिजिटल पहल है।

- नवनिर्मित MSTC कार्यालय, राजधानी में संगठन की भौतिक उपस्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। यह केंद्रीय स्थान MSTC को प्रमुख मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे नीतिगत संरेखण और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी।

- MSTC लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है, जो औद्योगिक और सरकारी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और नीलामी सेवाओं के लिए जाना जाता है।

- इस आधुनिक कार्यालय व्यवस्था से MSTC को संसाधन प्राप्ति और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मंचों पर, विशेष रूप से धातु, भारी उद्योग और अधिशेष इन्वेंट्री ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में, भागीदारी में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह बुनियादी ढाँचा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के इसके मुख्य कार्यों में गति और पारदर्शिता में सुधार के लिए तैयार किया गया है।

Key Points:-

(i) इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण MSTC द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बाज़ार, 'उपकरण' ई-पोर्टल का शुभारंभ था। इस पोर्टल को उद्योगों, MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) और सरकारी खरीदारों को जोड़ने वाले एक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे मशीनरी और

उपकरणों के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी लेनदेन संभव हो सके।

(ii) उपकरण प्लेटफ़ॉर्म उपकरण जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण डिजिटल समाधान है। इसमें अतिरिक्त या अप्रचलित मशीनरी और औद्योगिक संपत्तियों की सूचीकरण, स्थानांतरण, पुनर्विक्रय और निपटान जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को उपकरण लेनदेन को निर्बाध रूप से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे जवाबदेही और ऑडिट ट्रेल्स में सुधार होगा।

(iii) यह लॉन्च डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और व्यापार सुगमता के प्रति एमएसटीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खुले और कुशल मशीनरी व्यापार को बढ़ावा देकर, उपकरण पोर्टल एमएसएमई को बढ़ावा देने, फिजूलखर्ची को कम करने और पूरे भारत में सरकारी उपकरणों की खरीद और निपटान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।

7. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफ़ॉर्म पर 7 नए कृषि उत्पाद जोड़े, कुल संख्या 238 हुई।



जुलाई 2025 में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) प्लेटफ़ॉर्म में सात नए कृषि

उत्पाद जोड़े। इस कदम का उद्देश्य बाज़ार पहुँच, मूल्य प्राप्ति और व्यापार पारदर्शिता में सुधार करके किसानों की आय बढ़ाना है।

- नई जोड़ी गई कृषि जिंसों में गन्ना, मरचा चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और बनारसी पान शामिल हैं। इनके शामिल होने से, e-NAM पर व्यापार के लिए उपलब्ध जिंसों की कुल संख्या बढ़कर 238 हो गई है।

- ये सात उत्पाद विभिन्न राज्यों के विशिष्ट और GI-टैग वाले उत्पाद हैं। इनमें बिहार का सुगंधित और प्रीमियम चावल, बिहार के GI-टैग वाले आम और लीची, और बिहार तथा उत्तर प्रदेश दोनों के विशिष्ट पान के पत्ते शामिल हैं। इन उत्पादों को शामिल करने का उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देना और राज्यों के किसानों की बाज़ार पहुँच में सुधार करना है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने नए उत्पादों के लिए गुणवत्ता-आधारित व्यापार योग्य मानदंड और ग्रेड लागू किए हैं। ये मानदंड—जैसे अतिरिक्त श्रेणी, श्रेणी 1 और मूल्य श्रेणियाँ—एक समान मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

Key Points:-

(i) इसके अतिरिक्त, हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, पहले से जोड़ी गई चार वस्तुओं—सिंघाड़े का आटा, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट और मगही पान—के मौजूदा मानकों को संशोधित किया गया है। ये अद्यतन e-NAM नेटवर्क में बेहतर गुणवत्ता ग्रेडिंग और मानकीकृत मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देते हैं।

(ii) e-NAM (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) एक अखिल भारतीय डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 2016 में क्षेत्रीय कृषि बाज़ारों को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह किसानों को सशक्त बनाने के लिए वास्तविक समय मूल्य निर्धारण,

गुणवत्ता निर्धारण, पारदर्शी नीलामी और डिजिटल भुगतान निपटान को बढ़ावा देता है।

(iii) लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) e-NAM प्लेटफ़ॉर्म के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों तथा किसान समूहों के साथ समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करता है कि यह प्लेटफ़ॉर्म प्रासंगिक और समावेशी बना रहे।

8. ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मुंबई के ऐतिहासिक कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर 'सिंदूर ब्रिज' रखा गया।



जुलाई 2025 में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण मुंबई में नवनिर्मित कार्नेक ब्रिज का उद्घाटन किया और इसका नाम बदलकर "सिंदूर ब्रिज" कर दिया। यह नाम परिवर्तन औपनिवेशिक काल की विरासतों से एक प्रतीकात्मक प्रस्थान का प्रतीक है और भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि देता है, जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में सीमा पार आतंकवादी ढाँचों को निशाना बनाया था।

- मूल रूप से बॉम्बे के पूर्व ब्रिटिश गवर्नर (1839-1841) जेम्स रिचे-कार्नेक के नाम पर रखा गया यह

औपनिवेशिक काल का पुल भारतीय शासकों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ा रहा है।

● यह नाम परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक स्थलों से औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका समर्थन स्पीकर राहुल नावेंकर ने किया था और BMC ने भी इसका अनुमोदन किया था।

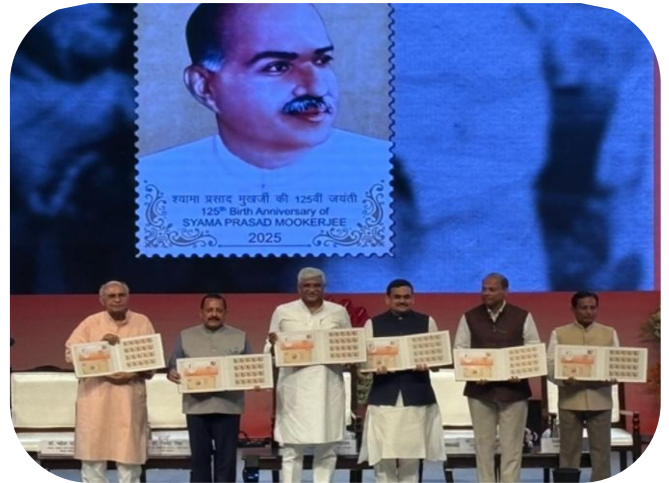
Key Points:-

(i) नया नाम ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में रखा गया है, जो मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक सटीक सैन्य अभियान था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को "करारा जवाब" बताया। नाम बदलने का उद्देश्य भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे में राष्ट्रीय शौर्य और रक्षा क्षमताओं को अमर बनाना है।

(ii) मूल 150 साल पुराने पुल को अगस्त 2022 में असुरक्षित घोषित कर तोड़ दिया गया था। मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार, BMC द्वारा पुनर्निर्मित, 342 मीटर लंबा नया सिंदूर पुल, जिसमें 70 मीटर का रेल-ओवर खंड भी शामिल है, चार लेन और आधुनिक स्टील गर्डरों से सुसज्जित है। यह सीएसटी, मस्जिद बंदर, क्रॉफर्ड मार्केट और मोहम्मद अली रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है—जिससे यात्रा का समय लगभग 30 मिनट कम हो जाता है।

(iii) जून 2025 में पूरा होने वाले इस पुल के गुप्त इंजीनियरिंग कार्य—जैसे अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में गर्डर लॉन्च—सक्रिय रेलवे लाइनों पर किए गए। 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे वाहनों के आवागमन के लिए खुलने से पहले, इसे भार परीक्षण, सुरक्षा और मध्य रेलवे अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।

9. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने ₹125 का सिक्का और ₹5 का डाक टिकट जारी किया।



9 जुलाई, 2025 को, संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (DoP) ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ₹125 का एक विशेष स्मारक सिक्का और ₹5 का एक डाक टिकट जारी किया। यह औपचारिक शुभारंभ नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें भारतीय राजनीति और शिक्षा में डॉ. मुखर्जी की विरासत को सम्मानित किया गया।

● इस लोकार्पण समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने भारतीय एकता और विचारधारा में डॉ. मुखर्जी के योगदान के राष्ट्रीय महत्व को उजागर किया।

● इस कार्यक्रम के साथ डॉ. मुखर्जी के योगदान के दो वर्षीय राष्ट्रीय स्मरणोत्सव अभियान की भी शुरुआत हुई, जो 6 जुलाई, 2025 से 6 जुलाई, 2027 तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

● ₹125 का यह स्मारक सिक्का 99.9% शुद्ध चाँदी से बना है, इसका वज़न 40 ग्राम और व्यास 44 मिमी है। इसके अग्रभाग पर अशोक का सिंह चिह्न अंकित है, जिस पर "सत्यमेव जयते" और द्विभाषी मूल्यवर्ग अंकित हैं, जबकि पृष्ठभाग पर डॉ. मुखर्जी का चित्र

अंकित है और उनके 125वें जन्म वर्ष को दर्शाने के लिए "1901-2026" अंकित है।

Key Points:-

(i) यह डॉ. मुखर्जी के सम्मान में जारी किया गया दूसरा स्मारक सिक्का है। पहला सिक्का अप्रैल 2002 में उनकी जन्मशती पर जारी किया गया था और यह ₹100, ₹50, ₹10 और ₹2 मूल्यवर्ग में उपलब्ध था। ये सिक्के अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण व्यापक रूप से प्रचलन में थे और संग्रहित किए गए थे।

(ii) सिक्के के साथ जारी किया गया ₹5 का डाक टिकट, नेनु गुप्ता द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसमें शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और मूल्य-आधारित शासन में डॉ. मुखर्जी की विरासत को दर्शाने वाले चित्र शामिल हैं। यह सांस्कृतिक गौरव पर आधारित आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है।

(iii) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 1901 में हुआ था, भारतीय जनसंघ (भाजपा के पूर्ववर्ती) के संस्थापक, एक दूरदर्शी शिक्षाविद् और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। यह सिक्का-टिकट विमोचन न केवल उनकी जयंती का स्मरण कराता है, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में उनके अमिट योगदान के बारे में युवाओं में जागरूकता भी जगाता है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और अर्जेंटीना में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद ब्राज़ील (5-8 जुलाई, 2025) और नामीबिया (एक दिवसीय यात्रा) की अपनी पाँच देशों की आधिकारिक यात्रा के चौथे और पाँचवें चरण का समापन किया। ब्राज़ील की यह यात्रा राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर हुई, जबकि नामीबिया यात्रा के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशन संपन्न हुआ।

● ब्राज़ील पहुँचने पर, प्रधानमंत्री मोदी का रियो डी जेनेरियो के गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने 6 से 7 जुलाई, 2025 तक आयोजित 17वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सदस्य देशों - ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका - के बीच आर्थिक सहयोग, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

● अपनी ब्राज़ील यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस में राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 20 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित करके भारत-ब्राज़ील संबंधों को मज़बूत करने का लक्ष्य रखा, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

Key Points:-

INTERNATIONAL

1. प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील और नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के साथ पाँच देशों की यात्रा संपन्न की।

(i) भारत-ब्राज़ील संबंधों को मज़बूत करने के लिए, राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'द ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का सम्मान करता है।

(ii) भारत और ब्राज़ील ने नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, डिजिटल अवसंरचना, सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

(iii) ब्राज़ील यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया का दौरा किया और राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह से मुलाकात की। भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य सेवा, खनिज अन्वेषण और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 4 नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एक महत्वपूर्ण सम्मान के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी को विंडहोक में एक राजकीय स्वागत समारोह के दौरान नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एंशिअंट वेल्विचिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया गया।



9 जुलाई, 2025 को, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने पेरिस में अपने 47वें सत्र के दौरान, आधिकारिक तौर पर तीन अफ्रीकी स्थलों को अपनी प्रसिद्ध खतरेग्रस्त विश्व धरोहर सूची से हटा दिया - जो वैश्विक धरोहर संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

● दुर्लभ लीमर प्रजातियों सहित अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए 2007 में घोषित, इस वर्षावन को 2010 में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई, कीमती लकड़ियों की तस्करी और वन आवरण के नुकसान के कारण खतरे की सूची में डाल दिया गया था। उपग्रह वन निगरानी, शिकार-विरोधी गश्त और स्थायी लकड़ी विनियमन जैसे समर्थित कार्यक्रमों के साथ, मेडागास्कर ने 63% खोए हुए वन आवरण को बहाल कर दिया है, बड़े पैमाने पर कटाई रोक दी है, और लीमर के अवैध शिकार में काफी कमी आई है।

● 1979 में उत्कीर्ण यह प्राचीन ईसाई तीर्थस्थल, आसपास की सिंचाई के कारण बढ़ते भूजल स्तर के कारण 2001 से खतरे में था, जिससे संरचनात्मक पतन हुआ। 2021 में स्थापित एक सौर ऊर्जा चालित जल निकासी प्रणाली और 2024 में एक व्यापक संरक्षण योजना ने जल स्तर को प्रभावी ढंग से कम किया, आगे की बर्बादी को रोका और संरचनात्मक अखंडता को मजबूत किया।

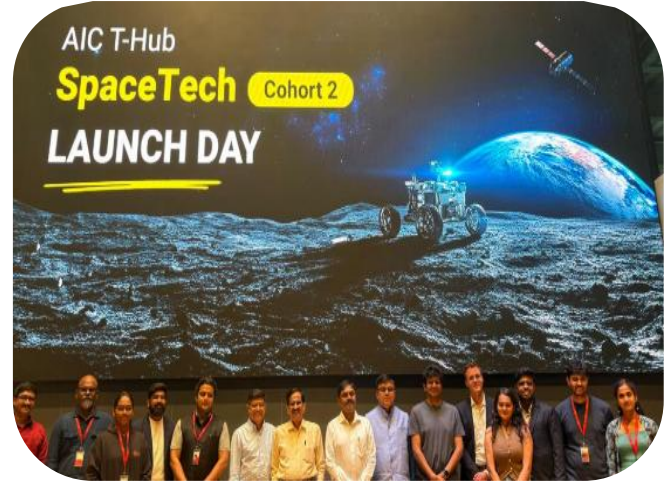
Key Points:-

2. UNESCO ने संरक्षण में बड़ी सफलता के बाद तीन अफ्रीकी विश्व धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया।

(i) 1986 से विश्व धरोहर स्थल, गदामेस, गृह संघर्ष, जंगल की आग और विनाशकारी बारिश के कारण 2016 से संकटग्रस्त सूची में था। पुनर्स्थापन प्रयासों—जिसमें इमारतों की मरम्मत, पाइपलाइनों का पुनर्वास और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना शामिल है—के साथ-साथ स्थानीय सामुदायिक प्रशिक्षण और जोखिम प्रबंधन पहलों ने अब इस स्थल को स्थिर कर दिया है।

(ii) UNESCO की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने इन निष्कासनों को विरासत संरक्षण के लिए एक "महान विजय" घोषित किया, और अफ्रीका पर यूनेस्को के रणनीतिक फोकस को रेखांकित किया: विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना, नए विरासत शिलालेखों का समर्थन करना, और लुप्तप्राय स्थलों के बचाव प्रयासों को बढ़ाना। 2021 से, चार अन्य अफ्रीकी स्थलों (कांगो गणराज्य, युगांडा, सेनेगल में) को भी सफलतापूर्वक सूची से हटा दिया गया है।

(iii) यह सूची अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता जुटाने, पुनर्स्थापन और निगरानी प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य करती है। पहचाने गए खतरों पर विजय पाने वाले स्थल, बढ़ी हुई धनराशि के लिए पात्र हैं, जैसा कि इन सफल संरक्षण पहलों से स्पष्ट होता है।



जुलाई 2025 में, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (AIM) द्वारा समर्थित T-Hub (प्रौद्योगिकी केंद्र) और AIC-T-Hub(अटल इनक्यूबेशन केंद्र - प्रौद्योगिकी केंद्र) ने "ऑर्बिट" स्पेसटेक एक्सेलरेटर कार्यक्रम का दूसरा समूह लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में 17 शुरुआती चरण के स्टार्टअप शामिल हुए हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा समूह बनाता है और वैश्विक स्पेसटेक पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करता है।

- AIC-T-Hub ऑर्बिट कार्यक्रम उपग्रह प्रणालियों, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष प्रणोदन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान, एयरोस्पेस निर्माण और गहन अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चयनित स्टार्टअप प्रोटोटाइप या एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) चरणों में हैं और वैश्विक मार्गदर्शन और संसाधन पहुँच के माध्यम से बाज़ार की तैयारी के लिए उन्हें विकसित किया जाएगा।

- इस समूह के स्टार्टअप्स को संरचित मार्गदर्शन, परीक्षण और निर्माण सुविधाओं तक पहुँच, नियामक सहायता और फ़ांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के भागीदारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्राप्त होंगे। यह समूह वित्त पोषण निकायों, नीति विशेषज्ञों और अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, जैसे कि ISRO

ECONOMY & BUSINESS

1. T-Hub ने 17 स्टार्टअप्स के साथ AIC-T-Hub "ऑर्बिट" स्पेसटेक एक्सेलरेटर का दूसरा समूह लॉन्च किया।

(भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र) से भी जुड़ेगा।

• इस कार्यक्रम में पूर्व DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, पूर्व इसरो वैज्ञानिकों और स्काईरूट एयरोस्पेस तथा ध्रुव स्पेस जैसी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिग्गजों के वरिष्ठ इंजीनियरों जैसी प्रमुख हस्तियों का मार्गदर्शन शामिल है। उनकी भागीदारी से स्टार्टअप्स को तकनीकी बाधाओं से निपटने और सटीकता के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

Key Points:-

(i) T-Hub के CEO कविकृत ने कहा कि ऑर्बिट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य समूह के अंत तक ₹3 करोड़ से अधिक का निवेश, 10 से अधिक बौद्धिक संपदाओं का सृजन और स्टार्टअप-लैब संबंधों में 15% की वृद्धि को सुगम बनाना है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप, शिक्षा जगत और सरकारी प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए अंतर-क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

(ii) ऑर्बिट एक्सेलरेटर के पहले समूह ने 10 स्पेसटेक स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान किया, जिनमें स्पांट्रिक, ओन्स क्रायोजेनिक्स, एनवीस लैब्स, तारामंडल और स्टेम एंड स्पेस शामिल हैं। इन स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद चैनलों, AIM-NITI आयोग नवाचार अनुदानों, और IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और सी-डैक (उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र) जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी का अवसर मिला।

2. दूरसंचार मिशन ने राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए केयरएक्सपर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



जुलाई 2025 में, मिशन के प्राथमिक दूरसंचार ऑपरेटर, टेलीकॉम इजिप्ट ने, रिलायंस जियो समर्थित भारतीय स्वास्थ्य-तकनीक कंपनी केयरएक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य मिशन में चिकित्सा पहुंच और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंच विकसित और लॉन्च करना है।

• मिशन के सुरक्षित, संप्रभु क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्लेटफॉर्म की मेजबानी के लिए, मिशन के काहिरा में आयोजित अफ्रीका हेल्थ एक्सकॉन 2025 सम्मेलन में इस समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया। यह कदम डेटा गोपनीयता और मरीजों के रिकॉर्ड के राष्ट्रीय स्वामित्व को सुनिश्चित करता है और साथ ही मिशन के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है।

• यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स (EMR) और राजस्व चक्र प्रबंधन (RCM) उपकरणों के साथ-साथ एक पूर्णतः एकीकृत अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) प्रदान करेगा। ये सुविधाएँ रोगी डेटा, बिलिंग, निदान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करके स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करेंगी।

Key Points:-

(i) क्लाउड-होस्टेड प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य देखभाल डेटा

तक वास्तविक समय तक पहुंच को सक्षम करेगा, डिजिटल-प्रथम अस्पतालों को बढ़ावा देगा, स्वास्थ्य देखभाल बिलिंग को सरल बनाएगा, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करेगा और मिस्र के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों में डेटा-संचालित नैदानिक निर्णय लेने की अनुमति देगा।

(ii) यह समझौता ज्ञापन मिस्र के विज्ञान 2030 के अनुरूप है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से सतत डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा मानकों में सुधार के लिए भारत-मिस्र स्वास्थ्य-तकनीक सहयोग को दर्शाता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. प्रिया नायर 1 अगस्त 2025 से HUL की पहली महिला CEO और MD बनने के लिए तैयार हैं।



भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने प्रिया नायर को अपना नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इस तरह, वह कंपनी के 92 साल के इतिहास में कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह रोहित जावा का स्थान लेंगी, जो दो साल के कार्यकाल

के बाद 31 जुलाई 2025 को पद छोड़ रहे हैं, जो कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में सबसे छोटे कार्यकालों में से एक है।

• यूनिलीवर और HUL में अपने लगभग 30 साल के करियर के दौरान, प्रिया नायर ने प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें कार्यकारी निदेशक - होम केयर (2014-2020), कार्यकारी निदेशक - सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल (2020-2022), और वैश्विक मुख्य विपणन अधिकारी, सौंदर्य और कल्याण (2023) शामिल हैं।

• जनवरी 2024 से, वह यूनिलीवर में ब्यूटी एंड वेलबीइंग डिवीजन की अध्यक्ष हैं, जो भारत और वैश्विक बाजारों में परिवर्तन ला रही हैं।

Key Points:-

(i) बोर्ड के अध्यक्ष नितिन परांजपे ने उनकी नियुक्ति की सराहना की, तथा नायर को "गहरी उपभोक्ता अंतर्दृष्टि वाली एक विश्व स्तर पर सम्मानित विपणक" बताया और एचयूएल को अगले विकास चरण में नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।

(ii) यह नेतृत्व परिवर्तन HUL के उच्चतम स्तर पर आंतरिक प्रतिभा, नवाचार और लैंगिक विविधता पर निरंतर जोर को दर्शाता है।

(iii) प्रिया नायर की पदोन्नति भारतीय उद्योग जगत में व्याप्त बाधाओं को तोड़ने में एक प्रमुख मील का पत्थर है, जहां महिलाएं सी-सूट भूमिकाओं में 20% से भी कम पदों पर हैं।

SPORTS

1. भारत नई दिल्ली में ISSF विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा।



भारत को दो प्रमुख वैश्विक निशानेबाजी स्पर्धाओं - ISSF विश्व कप 2027 और ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2028 - की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। दोनों स्पर्धाएँ नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी और इनसे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

- ISSF (अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ) ने पुष्टि की है कि नई दिल्ली 2027 ISSF विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निशानेबाज़ टूर्नामेंटों में से एक है। इस आयोजन में लगभग 70 देशों के 500 से ज़्यादा शीर्ष निशानेबाज़ राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में होना है, जो 2024 में ISSF विश्व कप फ़ाइनल सहित कई वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लिए जाना जाता है।

- भारत ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2028 की भी मेजबानी करेगा, जिससे यह पहली बार होगा जब यह आयोजन देश में आयोजित किया जाएगा। इस चैम्पियनशिप में दुनिया भर के अंडर-21 एथलीट विभिन्न टीम और व्यक्तिगत निशानेबाजी श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली में लगभग आठ दिनों तक चलने की उम्मीद है और भारत के उभरते निशानेबाजों के लिए एक प्रमुख वैश्विक प्रदर्शन अवसर के रूप में कार्य करेगा।

- इन निर्णयों को 10 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ISSF कार्यकारी समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। ये घोषणाएँ भारत को हाल ही में आवंटित कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के बाद की गई हैं, जिनमें सितंबर 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप, फरवरी 2026 में एशियाई राइफल/पिस्टल कप और नवंबर 2025 में भारतीय शूटिंग लीग शामिल हैं, जो निशानेबाजी खेलों के संचालन और बुनियादी ढाँचे में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के नेतृत्व में इन मेज़बानी अधिकारों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संगठन इन वैश्विक आयोजनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ मिलकर काम कर रहा है। एनआरएआई के महासचिव के. सुल्तान सिंह ने कहा कि भारत की सफल बोली ISSF के भारत की खेल क्षमताओं में विश्वास को दर्शाती है।

(ii) केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ISSF के इस निर्णय का स्वागत किया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये आयोजन "उत्कृष्टता की एक नई धारा" तैयार करेंगे और पूरे भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देंगे। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों से पहले प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी भारत की ओलंपिक तैयारी रणनीति के अनुरूप है, जिससे एथलीटों को घरेलू धरती पर शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

(iii) इन उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से निशानेबाजी खेलों के बुनियादी ढाँचे, अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण में पर्याप्त निवेश होने की उम्मीद है। 2028 तक हर साल कम से कम एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी आयोजन आयोजित करने के उद्देश्य से, भारत रणनीतिक रूप

से खुद को निशानेबाजी खेलों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, युवा एथलीटों को सशक्त बना रहा है और भविष्य के ओलंपिक खेलों में पदक की संभावनाओं को बढ़ा रहा है।

2. लॉर्ड्स MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया।



जुलाई 2025 में, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सम्मानित किया गया, जब इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरे टेस्ट से पहले मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) संग्रहालय में भारतीय सफेद पोशाक में उनका एक नया चित्र अनावरण किया गया।

• ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट द्वारा निर्मित यह चित्र 18 साल पहले सचिन के मुंबई स्थित घर में खींची गई एक तस्वीर पर आधारित है। घिसे हुए एल्युमीनियम पर तेल से रंगा यह चित्र एक अमूर्त पृष्ठभूमि के सामने सिर और कंधों की एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करता है जो कालातीत क्रिकेट उत्कृष्टता का प्रतीक है।

• तेंदुलकर MCC के प्रतिष्ठित चित्र संग्रह में शामिल होने वाले पाँचवें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं—कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, दिलीप वेंगसरकर और अन्य क्रिकेटरों के साथ। पिछली पूर्ण-लंबाई वाली श्रद्धांजलियों के विपरीत, इस चित्र का विशाल

आकार क्रिकेट इतिहास में उनके प्रतिष्ठित कद को रेखांकित करता है।

• तेंदुलकर ने लॉर्ड्स के साथ अपने गहरे जुड़ाव पर बात की और 1988 और 1989 में स्टार क्रिकेट क्लब के साथ किशोरावस्था में अपनी शुरुआती यात्राओं को याद किया। उन्होंने इस अनुभव को "जीवन का एक चक्र पूरा होने" जैसा बताया और इस भावनात्मक उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त किया।

Key Points:-

(i) अनावरण के बाद, तेंदुलकर ने पाँच मिनट के प्रतिष्ठित घंटी बजाने के समारोह में भाग लिया, जो लॉर्ड्स में महान क्रिकेटरों के सम्मान में आयोजित एक प्रतिष्ठित परंपरा है। इस अवसर पर उन्होंने पहली बार घंटी बजाई, जिसका खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों ने समान रूप से स्वागत किया।

(ii) यह अनावरण नए नाम वाले एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के साथ हुआ, जिसमें घरेलू मैदान पर सचिन के शानदार टेस्ट रिकॉर्ड और महान इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया।

(iii) लॉर्ड्स का चित्र कार्यक्रम, जो विक्टोरियन युग से ही किसी न किसी रूप में मौजूद है, और यूरोप के सबसे पुराने खेल संग्रहालय, MCC संग्रहालय में अब 3,000 से ज़्यादा कलाकृतियों के संग्रह में लगभग 300 क्रिकेट चित्र मौजूद हैं। तेंदुलकर का चित्र इस साल के अंत में पवेलियन में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा।

AWARDS

1. तेलंगाना ने बैटरी विनिर्माण में नेतृत्व के लिए IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।



जुलाई 2025 में, तेलंगाना को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (IESA) द्वारा राज्य नेतृत्व - बैटरी निर्माण श्रेणी में प्रतिष्ठित IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित 11वें इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक (IESW) के दौरान प्रदान किया गया।

● बैटरी निर्माण केंद्र के रूप में तेलंगाना का उदय, तेलंगाना ईवी एवं ऊर्जा भंडारण नीति और तेलंगाना नवीकरणीय ऊर्जा नीति जैसी सक्रिय सरकारी नीतियों का परिणाम है। इन पहलों ने, औद्योगिक क्लस्टर जैसे बुनियादी ढाँचे की स्थापना के साथ, बैटरी निर्माण और ईवी असेंबली से लेकर प्रमुख घटकों के उत्पादन तक, संपूर्ण बैटरी मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित किया है।

● तेलंगाना में कई बड़े पैमाने की परियोजनाएँ शुरू हो गई हैं: महबूबनगर में अमारा राजा की गीगाफैक्ट्री ₹9,500 करोड़ के निवेश से 16GWh लिथियम-आयन सेल और 5GWh बैटरी पैक का उत्पादन करेगी। इसके अतिरिक्त, GODI इंडिया ने ₹8,000 करोड़ के निवेश से 12.5GWh बैटरी सेल प्लांट की योजना की घोषणा की है।

● सरकार समर्थित बुनियादी ढाँचे द्वारा रणनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया गया है: मार्च 2025 में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर

(EMC) में चार विनिर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी, जिसमें बैटरी सेल आवरण, खनिज शोधन, पुनर्चक्रण और एक LFP-CAM गीगा फैक्ट्री के लिए समर्पित सुविधाएं शामिल हैं।

Key Points:-

(i) ऊर्जा भंडारण में तेलंगाना का नेतृत्व विनिर्माण से आगे तक फैला हुआ है। तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा मार्च 2025 में आयोजित राज्य के 250MW/500MWh बैटरी स्टोरेज टेंडर ने प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आकर्षित कीं, जिससे ग्रिड-स्केल स्टोरेज समाधानों की मज़बूत माँग का संकेत मिलता है। बोंडाडा इंजीनियरिंग, पेस डिजिटैक और टूआरई-ओरियाना पावर जैसी संस्थाओं ने अनुबंध हासिल किए, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में राज्य की भूमिका और मज़बूत हुई।

(ii) उद्योग जगत के नेता प्रोत्साहनों, सुव्यवस्थित अनुमोदनों, भूमि उपलब्धता और समर्पित क्लस्टरों सहित एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण पर तेलंगाना के निरंतर ध्यान की सराहना करते हैं। तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय दूरदर्शिता और हितधारक सहयोग को दिया।

(iii) भविष्य की ओर देखते हुए, तेलंगाना का लक्ष्य विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देकर, बैटरी तकनीक (सोडियम-आयन और सॉलिड-स्टेट वेरिएंट सहित) में नवाचार करके और कुशल कार्यबल का निर्माण करके भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान में अपनी भूमिका को और मज़बूत करना है। IESA सम्मान न केवल पिछली उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि ऊर्जा भंडारण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने के तेलंगाना के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाता है।

2. प्राजक्ता कोली को TIME100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय नामित किया गया।



जुलाई 2025 में, यूट्यूबर से अभिनेता बनी प्राजक्ता कोली - जिन्हें ऑनलाइन मोस्टलीसेन के नाम से जाना जाता है - ने TIME पत्रिका की उद्घाटन टाइम 100 क्रिएटर्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारत में जन्मी रचनाकार के रूप में इतिहास रचा, जिसमें मिस्टरबीस्ट और जय शेटी जैसे वैश्विक आइकन के साथ दुनिया की सबसे प्रभावशाली डिजिटल आवाज़ें प्रदर्शित हुईं।

- प्राजक्ता का समावेश उनकी वैश्विक पहचान को रेखांकित करता है, उनके 7 मिलियन से अधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर और 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो उनके प्रासंगिक कॉमेडी स्केच, वकालत और सम्मोहक कहानी कहने की क्षमता के कारण है।

- एक बहुआयामी प्रतिभा, वह नेटफ्लिक्स की हिट श्रृंखला मिसमैच की मुख्य भूमिका में हैं, उनका पहला उपन्यास 'टू गुड टू बी टू' सबसे ज्यादा बिकने वाला है, और वह जलवायु सक्रियता में सक्रिय हैं - UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में सेवा कर रही हैं।

Key Points:-

(i) रेडियो इंटरन से लेकर वैश्विक प्रभावशाली व्यक्ति तक प्राजक्ता की यात्रा में यूट्यूब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज "क्रिएटर्स फॉर चेंज" के लिए डेटाईम एमी पुरस्कार जीतना, विश्व आर्थिक मंच जैसे उच्च

स्तरीय मंचों में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, संयुक्त राष्ट्र और गेट्स फाउंडेशन के साथ जुड़ाव शामिल है।

(ii) अपने वक्तव्य में, उन्होंने इस मान्यता को "विनम्र और सार्थक" बताया, तथा जलवायु कार्रवाई, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए अपने मंच का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई।

(iii) यह उपलब्धि न केवल कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में प्राजक्ता कोली के उत्थान को उजागर करती है, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक सक्रियता परिदृश्य में वैश्विक प्रभाव स्थापित करने वाले भारतीय डिजिटल रचनाकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का भी प्रतिनिधित्व करती है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व अश्व दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई 2025 को मनाया गया।



विश्व अश्व दिवस, जो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, मनुष्यों और घोड़ों के बीच के अटूट बंधन का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 2025 में संकल्प 79/291 के माध्यम से स्थापित, यह दिवस कृषि, परिवहन, संस्कृति, चिकित्सा और

अर्थव्यवस्था में घोड़ों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2025 को अपने 79वें सत्र में इस प्रस्ताव को पारित किया, जिसके पक्ष में 169, विपक्ष में 1 (संयुक्त राज्य अमेरिका) और किसी भी मतदान में कोई मतदान नहीं हुआ। मंगोलिया द्वारा प्रायोजित और ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, जापान, कतर और तुर्की सहित 56 देशों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में घोड़ों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 जुलाई को विश्व अश्व दिवस घोषित किया गया है।

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से प्राप्त संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व में लगभग 57 मिलियन घोड़ों का उपयोग घुड़सवारी, ड्राफ्ट कार्य, रेसिंग, खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य उत्पादन में किया जाता है।

- अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 63,000 फार्मों (2022 USDA) में 2.41 मिलियन घोड़े हैं, जबकि यूरोपीय संघ के अश्वारोही क्षेत्र में लगभग 7 मिलियन घोड़े हैं और 800,000 नौकरियाँ हैं। मंगोलिया के खानाबदोश समुदायों में घोड़ों और लोगों का अनुपात लगभग एक-से-एक है, जहाँ 3.3 मिलियन की आबादी पर 3.4 मिलियन घोड़े हैं।

Key Points:-

(i) विश्व अश्व दिवस एक कार्रवाई का आह्वान है, जो सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों, स्कूलों और व्यक्तियों से कल्याणकारी पहलों, अनुसंधान, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण में संलग्न होने का आग्रह करता है। यह घोड़ों के लिए प्रमुख खतरों पर भी प्रकाश डालता है, जिनमें आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन (2024 +1.5°C से ऊपर तापमान वृद्धि वाला पहला वर्ष होगा), आर्थिक तनाव और तकनीकी विस्थापन शामिल हैं।

यह प्रस्ताव अश्वपालन, जलवायु-अनुकूल प्रोटोकॉल

(जैसे घुड़सवारी कार्यक्रमों में लेन को धुंधला करना) जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और घोड़ों पर निर्भर ग्रामीण आजीविका के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करता है।

(iii) अंततः, विश्व अश्व दिवस घोड़ों के बहुमुखी योगदान को रेखांकित करता है—स्थायी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक विरासत और चिकित्सा तक। बचाव केंद्रों के दौरे, धन उगाहने, शिक्षा, खेल और कल्याणकारी वकालत में संलग्न होकर, वैश्विक समुदाय इन राजसी जानवरों के कल्याण की रक्षा और हमारी साझा विरासत में उनकी आवश्यक भूमिका को संरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ाता है।

2. विश्व जनसंख्या दिवस 2025, 11 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा।



विश्व जनसंख्या दिवस 2025, वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों और उनके बहुआयामी प्रभावों को उजागर करने के लिए 11 जुलाई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 1989 में स्थापित, यह तिथि उस ऐतिहासिक मील के पथर को चिह्नित करती है जब 11 जुलाई, 1987 को वैश्विक जनसंख्या पाँच अरब तक पहुँच गई थी, जिसे "पाँच अरब दिवस" के रूप में जाना जाता है।

● इस वर्ष का विषय है, "युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना।" यह युवा एजेंसी, प्रजनन अधिकारों, लैंगिक समानता और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर ज़ोर देता है, और नीति-निर्माताओं से आज की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी के लिए सूचित विकल्पों और समान समर्थन को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है।

Key Points:-

(i) विश्व जनसंख्या दिवस आज पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है: वैश्विक जनसंख्या 8.2 अरब को पार कर चुकी है और सदी के मध्य तक लगभग 10 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है, संसाधनों की कमी, वृद्ध होते समाज और घटती जन्म दर जैसी चुनौतियाँ तत्काल नीतिगत प्रतिक्रिया की माँग करती हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता को कार्रवाई में बदलना, सतत विकास, परिवार नियोजन और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।

(ii) अपनी शुरुआत के बाद से, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और युवा समूहों को शामिल करते हुए एक वैश्विक मंच बन गया है। इसके आयोजनों में सेमिनार, स्वास्थ्य शिविर, वकालत अभियान और समुदाय-संचालित पहल शामिल हैं - जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी और टिकाऊ समाजों को बढ़ावा देने के इसके मिशन को और मज़बूत करते हैं।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. ISRO ने तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि में गगनयान के SMPS का हॉट टेस्ट आयोजित किया।



जुलाई 2025 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने महेन्द्रगिरि, तमिलनाडु (तमिलनाडु) स्थित ISRO प्रणोदन परिसर (IPRC) में गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली (SMPS) के दो अल्पकालिक ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किए। ये ताप परीक्षण क्रमशः 30 सेकंड और 100 सेकंड तक चले, और प्रणोदन प्रणाली के सभी परीक्षण मानदंडों को पूरा करके उसके प्रदर्शन की पुष्टि की।

● सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम (SMPS), गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल (OM) का एक अनिवार्य तत्व है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान कक्षीय गतिविधियों को अंजाम देने और विशिष्ट निरस्तीकरण परिदृश्यों को संभालने के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें मिशन सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत थ्रस्टर्स का एक संयोजन शामिल है।

● SMPS में पाँच लिक्विड एपोजी मोटर (LAM) इंजन और सोलह रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (RCS) थ्रस्टर्स शामिल हैं। ये कक्षीय समायोजन और कक्षा में संचालन के लिए आवश्यक थ्रस्ट और दिशात्मक नियंत्रण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

● SMPS का विकास और परीक्षण द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) द्वारा किया जा रहा है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। एलपीएससी भारत के अंतरिक्ष अभियानों में

प्रयुक्त सभी द्रव प्रणोदन प्रणालियों के डिज़ाइन, विकास और योग्यता निर्धारण के लिए ज़िम्मेदार है।

Key Points:-

(i) 100-सेकंड की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान, ISRO ने 5 LAM इंजनों को एक साथ फायर किया, जिससे 440 न्यूटन (N) का बल उत्पन्न हुआ, साथ ही 16 RCS थ्रस्टर्स को भी फायर किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने 100 N थ्रस्ट उत्पन्न किया। इन परीक्षणों को स्थिर अवस्था (steady-state) और पल्स मोड (pulsed mode) दोनों में किया गया।

(ii) गगनयान मिशन, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में भेजना है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

Static GK

the TIME Magazine	प्रधान संपादक : सैम जैकब्स	मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
ISRO	अध्यक्ष: वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु
Punjab	राजधानी: चंडीगढ़	मुख्यमंत्री: भगवंत मान
Uttarakhand	मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी	राज्यपाल: गुरमित सिंह
MSTC (Metal Scrap Trade Corporation) Limited	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : मनोबेंद्र घोषाल	मुख्यालय : कोलकाता, पश्चिम बंगाल
MoA&FW	केंद्रीय मंत्री: शिवराज सिंह चौहान	मुख्यालय: नई दिल्ली
UNESCO	महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले	मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस